Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

फरवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि और महिला सशक्तीकरण योजना लागू 3
- छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिली माओवादियों की सुरंग 3
- राज्य में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार 4
- छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों का विस्तार 5
- छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया 5
- छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन 6
- छत्तीसगढ़ में 'नियद नेल्लानार' लॉन्च किया जाएगा 6
- पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई 7
- छत्तीसगढ़ कोरबा में एल्युमीनियम पार्क परियोजना को पुनर्जीवित करेगा 8
- प्रधानमंत्री ने ट्रेन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी 9

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि और महिला सशक्तीकरण योजना लागू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए करने और 'महतारी वंदन' योजना लागू करने का निर्णय लिया।

मुख्य बिंदु:

- कैबिनेट बैठक में सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' (Mahtari Vandan Yojana) को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
  - इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को समाप्त करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है।
  - लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा जो 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ भी योजना के लिये पात्र हैं।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक नई योजना लागू की जाएगी, जिसमें 75% वित्तीय सहायता सरकार द्वारा और शेष 25% छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ द्वारा प्रदान की जाएगी।
- मंत्रिमण्डल ने छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (BH) श्रृंखला वाहन पंजीयन लागू करने का भी निर्णय लिया है।
  - भारत सरकार द्वारा लागू की गई BH श्रृंखला के तहत दोपहिया और चौपहिया वाहनों को एक बार में दो साल का टैक्स देना होगा।
- छत्तीसगढ़ वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिली माओवादियों की सुरंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में माओवाद प्रभावित बीजापुर में एक ऑपरेशन से लौट रहे सैनिकों को नक्सलियों द्वारा खोदी गई 130 फीट लंबी सुरंग का पता चला है।

मुख्य बिंदु:

- लगभग दो दशक पहले उग्रवाद शुरू होने के बाद से यह बस्तर में इस तरह की पहली खोज है और इसने उग्रवाद विरोधी अभियानों में जटिलता की एक परत जोड़ दी है।
- ज़िला रिज़र्व गार्ड के जवानों को रायपुर से लगभग 330 किमी. दक्षिण में इंद्रावती के तट पर ताड़ोपोट गाँव के पास सुरंग मिली।
- ऐसी सुरंग की खोज से संकेत मिलता है कि माओवादी सुरक्षा अभियानों और हवाई निगरानी को तेज़ करने से निपटने के लिये रणनीति बदल रहे हैं।

भारत में वामपंथी उग्रवाद

- वामपंथी उग्रवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादियों के रूप में और भारत में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है।
- नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलबाड़ी से लिया गया है। इसकी शुरुआत स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी।

- विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी।
- यह आंदोलन छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में फैल गया है।
- यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
  - माओवाद, साम्यवाद का एक रूप है जो माओत्सेतुंग द्वारा विकसित किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने में विश्वास रखते हैं।

राज्य में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के साथ बैठक के दौरान, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं में केंद्र के योगदान को बढ़ाने का आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु:

- छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में से केवल 16 ज़िलों में केंद्र द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है।
- समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना और मिड-डे मील जैसी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय बोझ केंद्र एवं राज्य क्रमश: 40% व 60% के विभाजन के साथ साझा करते हैं।
- राज्य ने इन कार्यक्रमों में केंद्र के योगदान में वृद्धि का अनुरोध किया।
- राज्य ने विशेष रूप से केंद्र से समग्र शिक्षा योजना के तहत लाइका संवर योजना के लिये 2,606 लाख रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसमें प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक की शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 110.86 लाख रुपए शामिल हैं।
- राज्य ने केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM USHA) के पोर्टल को फिर से खोलने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना है।
- उच्च शिक्षा के लिये केंद्र सरकार की योजनाओं में फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया गया है।

समग्र शिक्षा योजना

- यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा को शामिल करती है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं को शामिल किया गया है।

पीएम-श्री योजना

- यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत करना है।

मध्याह्न भोजन योजना

- यह शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है।
- इसे वर्ष 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है।
- इसमें प्रावधान है कि कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो स्कूल में दाखिला लेता है और उपस्थित होता है, को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला गर्म पका हुआ भोजन ,स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन प्रदान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय में कई खदानों के विस्तार और उद्घाटन तथा असम के वन्यजीव समृद्ध दोयांग आरक्षित वन में खोजपूर्ण ड्रिलिंग के लिये "सैद्धांतिक" मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- इनमें से तीन खदानें छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में हैं। ये हैं– गेवरा खदान, कुसमुंडा खदान और दीपका ओपनकास्ट कोयला खदान।
- छत्तीसगढ़ में, FAC ने "सैद्धांतिक" अनुमोदन की सिफारिश की:
  - गेवरा खदान के विस्तार के लिये अतिरिक्त 94.293 हेक्टेयर वन के डायवर्जन हेतु।
  - कुसमुंडा खदान के विस्तार के लिये अतिरिक्त 43.942 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिये।
    - कुसमुंडा ओपनकास्ट खदान हसदेव की सहायक नदी के निकट बहती है जो इसे विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाती है।
  - कोरबा के कटघोरा वन में अतिरिक्त 0.093 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्ज़न के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (SECL) दीपका ओपनकास्ट कोयला खदान को।
- FAC ने सिफारिश की है कि छत्तीसगढ़ सरकार जलग्रहण क्षेत्र का उपचार सुनिश्चित करे और SECL को हसदेव नदी के संरक्षण के लिये जल संसाधन विभाग द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने का निर्देश दे।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee- FAC)

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 द्वारा किया गया था।
- FAC 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत कार्य करती है।
- यह समिति गैर-वन उपयोगों जैसे- खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिये वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंज़ूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है। हालाँकि इसकी भूमिका सलाहकारी है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)

- SECL भारत की सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनी है। SECL की कोयला खदानें दो राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं।
- यह 65 कोयला खदानों का संचालन करती है, जिनमें से 39 कोयला खदानें छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, जबकि शेष 26 कोयला खदानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन 65 कोयला खदानों में से 46 खदानों में खनन की भूमिगत विधि से कार्य किया जाता है जबकि बाकी 19 खदानें ओपनकास्ट खदानें हैं।

हसदेव नदी

- हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- हसदेव के वन, हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध का जलग्रहण क्षेत्र भी हैं, जो छह लाख एकड़ भूमि को सिंचित करता है और मुख्य फसल धान वाले राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, समृद्ध जैवविविधता और हाथियों के लिये एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण वन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिये 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु:

- बजट ज्ञान-गरीब (गरीब), युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिला) के आर्थिक विकास पर केंद्रित है, इसमें पूंजीगत व्यय में वृद्धि करके बुनियादी ढाँचे के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ युवाओं के लिये रोज़गार तथा आजीविका को बढ़ावा दिया गया है।
- राज्य को विकासशील से विकसित राज्य में बदलने के उद्देश्य से 1 नवंबर, 2024 को 'अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047' नामक एक दस्तावेज़ लोगों को समर्पित किया जाएगा।
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) अगले पाँच वर्षों में वर्ष 2028 तक 5 लाख करोड़ रुपए से दोगुना होकर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो इसमें उल्लिखित दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में पहला मध्यावधि लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ ने राजनांदगाँव ज़िले के ढाबा गाँव के पास स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाले देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है।

- इसकी स्थापना भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा की गई है और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी 100 मेगावाट की क्षमता प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु:

- यह सौर संयंत्र सुनिश्चित करता है कि रात के दौरान भी विद्युत रहेगी और प्रतिदिन पाँच लाख यूनिट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी।
  - इससे 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) द्वारा स्थापित ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र सतत् ऊर्जा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह संयंत्र 1 फरवरी, 2024 को स्थापित किया गया था। इसमें 2,39,000 बाइफेशियल सोलर पैनलों से सुसज्जित 100 मेगावाट का सौर संयंत्र है जो दोनों तरफ से विद्युत का उत्पादन कर रहा है।
- इस संयंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके अगले सात वर्षों तक विद्युत उत्पन्न करने की उम्मीद है।
- राजनांदगाँव ज़िले के बैरम पहाड़ी क्षेत्र में पहला सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के लिये इन पहाड़ी इलाकों का अधिकतम उपयोग करने हेतु लिया गया था।
  - परियोजना वर्ष 2016 में शुरू हुई, जिसमें पहले चरण में पाँच गाँव और 181.206 हेक्टेयर तथा दूसरे चरण में चार गाँव एवं 196-217 हेक्टेयर शामिल थे।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI)

- इसकी स्थापना वर्ष 2011 में राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM) के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये की गई थी।
- SECI को शुरुआत में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 25 कंपनी (गैर-लाभकारी) के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2015 में, इसे धारा -3 कंपनी में बदल दिया गया था।
- SECI एक अनुसूची-A केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है। यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षेत्र के विकास के लिये समर्पित एकमात्र CPSU है और इसकी गतिविधियों का दायरा सभी संसाधनों को कवर करता है।

छत्तीसगढ़ में 'नियद नेल्लानार' लॉन्च किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के अनुसार, राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिये जल्द ही 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू करने जा रही है।

- इन गाँवों को केंद्र के पीएम-जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएँ मिलेंगी, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है।

मुख्य बिंदु:

- नियद नेल्लानार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" या "योर गुड विलेज" स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
  - बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इन गाँवों के परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत चार निशुल्क गैस सिलेंडर, निशुल्क चावल, चना-नमक, गुड़ और चीनी, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, निशुल्क बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी तथा वन अधिकार प्रमाण-पत्र मिलेंगे।
- बारहमासी सड़कों के अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, खेल मैदान, बैंक, ATM, मोबाइल टावर, हेलीपैड आदि का निर्माण कराया जायेगा।

उज्ज्वला योजना

- परिचय:
  - यह वर्ष 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) या उज्ज्वला 2.0 योजना का दूसरा चरण है।
- उद्देश्य:
  - महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
  - भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
  - जीवाश्म ईंधन जलाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को बचाना।

पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना लॉन्च की।

मुख्य बिंदु:

- पीएम श्री योजना के पहले चरण में, छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों (193 प्राथमिक स्तर और 18 माध्यमिक) को प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपए खर्च करके 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा।
- मॉडल के तहत, 'हब' नामक सलाहकार संस्थान को केंद्रीकृत किया जाएगा और आत्म-सुधार के लिये सलाहकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से 'स्पोक' की माध्यमिक शाखाओं के माध्यम से सलाहकार संस्थान का मार्गदर्शन करने की ज़िम्मेदारी होगी।
- सीएम के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत केंद्र की योजना है कि वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का मौका मिलेगा।
  - अगस्त 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने हेतु पर्याप्त समय और अवसर है, बोर्ड परीक्षाएँ वर्ष में कम-से-कम दो बार आयोजित की जाएंगी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा।

पीएम श्री

- यह देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना है।

- इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत करना है।
- इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षण, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21 वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण भी होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

- NEP 2020 का लक्ष्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Global Knowledge Superpower)" बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है।
  - पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
  - नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) क्रमश: 3-8, 8-11, 11-14 एवं 14-18 वर्ष के आयु समूहों से सुमेलित है।
  - इसमें स्कूली शिक्षा के चार चरण शामिल हैं: मूलभूत चरण (5 वर्ष), प्रारंभिक चरण (3 वर्ष), मध्य चरण (3 वर्ष) और माध्यमिक चरण (4 वर्ष)।
  - कला तथा विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं।
  - बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
  - एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना।
  - वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये एक भिन्न लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र।

छत्तीसगढ़ कोरबा में एल्युमीनियम पार्क परियोजना को पुनर्जीवित करेगा

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरबा में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मूल रूप से वर्ष 2021 में प्रस्तावित एल्यूमीनियम पार्क प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को रियायती दर पर कच्चे एल्युमीनियम की आपूर्ति करने के लिये वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के साथ एक समझौता किया था।
- ज़िला प्रशासन ने परियोजना के लिये बाल्को टाउनशिप के पास रुखबहारी गाँव की ज़मीन की पहचान की और यहाँ तक कि परियोजना के लिये ग्रामीणों की सहमति लेने हेतु एक ग्राम सभा भी आयोजित की।
- कोरबा ज़िले में एल्यूमिनियम पार्क की मांग को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव में 5 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO)

- BALCO को वर्ष 1965 में भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के रूप में शामिल किया गया था और तब से यह प्रमुख रूप से भारतीय औद्योगिक विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
- वर्ष 2001 में भारत सरकार ने वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के 51% शेयरों का विनिवेश किया।

- BALCO निर्माण में स्टील और विद्युत् पारेषण उद्योग में कॉपर जैसी अन्य धातुओं के संभावित विकल्प के रूप में एल्युमीनियम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- BALCO का प्रमुख परिचालन कोरबा (छत्तीसगढ़) शहर में है, जबकि उच्च ग्रेड बॉक्साइट की आपूर्ति करने वाली इसकी खदानें कवर्धा और मैनपाट में स्थित हैं।

प्रधानमंत्री ने ट्रेन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 21 स्टेशनों और 83 रोड ओवर/अंडर ब्रिज के पुनर्विकास सहित कई रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु:

- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के अनुसार, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देशभर में 41,000 करोड़ रुपए की कुल 2,000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- इन स्टेशनों में से 21 स्टेशन छत्तीसगढ़ में आते हैं- कोरबा, रायगढ़, राजनांदगाँव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाईनगर, हथबंध, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, निपानिया , मंदिर हसौद और भिलाई।
  - ओडिशा में बेलपहाड़ और ब्रजराजनगर, मध्य प्रदेश में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बिजुरी, मंडला किला, बालाघाट, नैनपुर, छिंदवाड़ा , सिवनी तथा महाराष्ट्र में इतवारी, कैम्पटी, आमगाँव, भंडारा रोड एवं तुमसर रोड।

अमृत भारत स्टेशन योजना

- अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।
- यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ इंटर-मोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिये सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिये साइनेज़ (संकेतों के माध्यम से) सुविधा भी सुनिश्चित करेगा।
- यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)

- यह ज़ोन दक्षिण पूर्व रेलवे के विभाजन के बाद 1 अप्रैल 2003 को अस्तित्व में आया।
- इसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है तथा इसमें तीन डिवीज़न शामिल हैं: बिलासपुर, रायपुर और नागपुर।

✦ ✦ ✦ ✦